

## माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 (Secondary Education Commission)

### मुद्राबिम्ब आयोग

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) आयोग की नियुक्ति की गई थी परन्तु देश के शिक्षाविदों एवं विद्वानों का मत था कि माध्यमिक शिक्षा की भी जाँच की जाए और उसका पुनर्गठन पुनर्गठन किया जाय जिसके फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान प्रणाली की जाँच करने और उसके पुनर्गठन एवं सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए 23 सितम्बर 1952

को डॉ० एच० जेम्सरावानी मुद्राबिम्ब की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया । इसलिए इसे मुद्राबिम्ब आयोग भी कहा जाता है ।

### आयोग का प्रतिवेदन (Report of the commission)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान समस्याओं की विस्तृत जाँच की और अपने सुझावों एवं संस्तुतियों को 15 अध्यायों एवं 224 पृष्ठों में प्रतिवेदन तैयार किया जिसे 29 अगस्त 1953 ई० को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया ।

## आयोग के जॉन के विषय ०

भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति और इसके प्रत्येक पहलू की जांच करना और सुधार का सुझाव देना ।

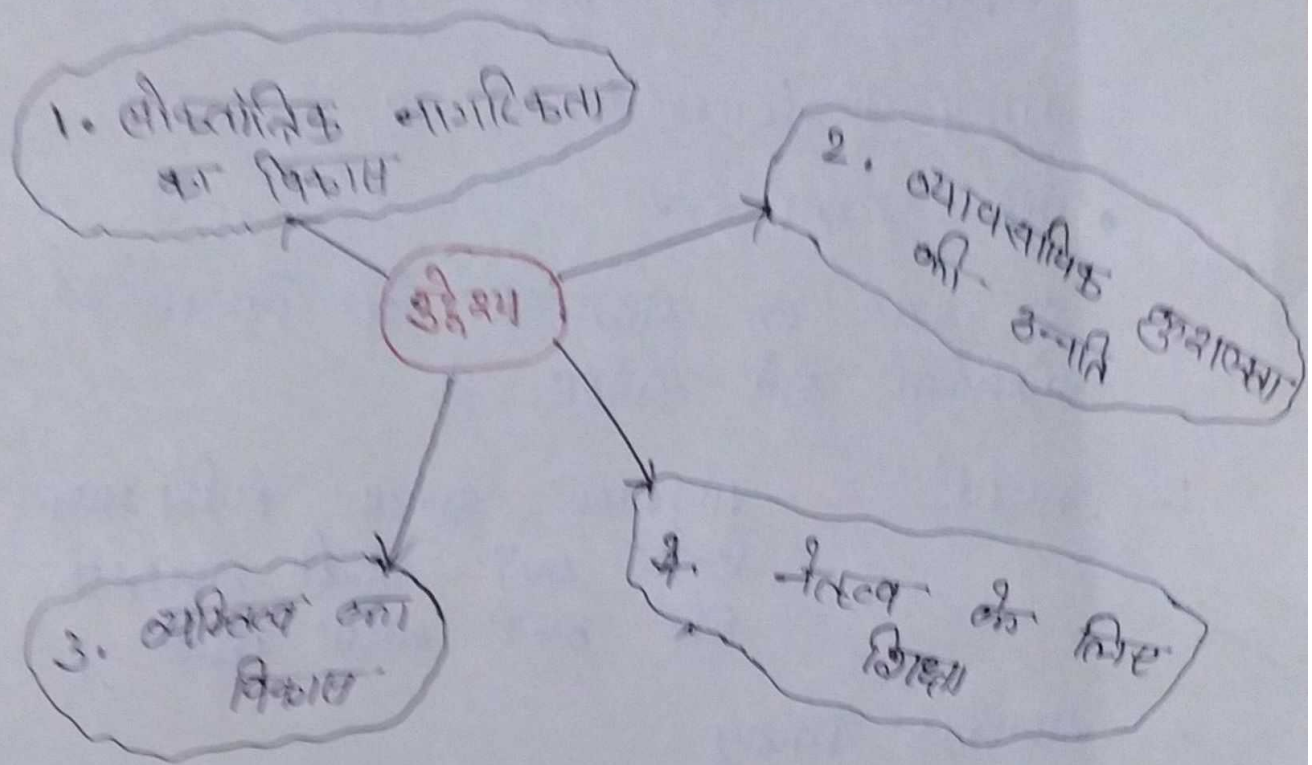
## आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियों ० (Suggestions and Recommendations of the Commission)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित दोषों का उल्लेख किया है —

1. यह संकीर्ण एवं एकांगी है और छात्रों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में असमर्थ है।
2. पाठ्यक्रम छात्रों को अपनाने का वातावरण के प्रति सख्त प्रदान नहीं करता है।
3. शिक्षण विधियाँ जो सामान्यतः व्यवहार में आ रही हैं स्वतः प्रेरणा में असफल रही हैं।
4. पढाई में छात्रों की संख्या में वृद्धि से शिक्षक एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क कम हुआ है इससे अनुशासन की दृष्टि में गम्भीर रूप से क्षति पहुँची है।
5. परीक्षाओं पर अधिक तब, परम्परागत पाठ्यक्रम, यांत्रिक और अजीबत शिक्षण विधियाँ और शिक्षा में गलत अथवा अनावश्यक बातों को लक्ष्य देने से शिक्षकों की स्वतः प्रेरणा को दबाने की नीति और मजबूर किया है।

माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य  
(Aims of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावित निम्नलिखित आयोग ने उद्देश्य



माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक स्वरूप इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियों प्रस्तुत की हैं।

1. माध्यमिक शिक्षा 4 अथवा 5 वर्ष की प्राथमिक या जूनियर तैलिक शिक्षा के बाद प्रारम्भ होनी चाहिए।
2. वर्तमान इण्टरमीडिएट स्तर को उन्नत माध्यमिक स्तर द्वारा जलन दिया जाना चाहिए।

3. जो उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिए व्यावसायिक कार्यों में प्रवेश खुले होने चाहिए।
4. सभी राज्यों के प्राचीन विद्यालयों में कृषि शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए और इन पाठ्यक्रमों में कपावानी, पशुपालन और कृषि उद्योग को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

### पाठ्यक्रम (Curriculum) $\frac{0}{0}$

#### • मिडिल स्कूल स्तर

इस स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होने चाहिए -

1. भाषाएँ - मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी जहाँ हिन्दी मातृभाषा है, वहाँ वहाँ अन्य भाषा पढ़ेंगी।
2. सामाजिक विज्ञान
3. सामान्य विज्ञान
4. गणित      5. कला तथा संगीत
6. श्रम      7. शारीरिक शिक्षा।

#### • उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर

कुछ निश्चित संख्या में कोर विषय सभी वर्गों के लिए सामान्य होने चाहिए जिससे वे अध्ययन के लिए विभिन्न पाठ्यविषयों को ले सकें।

## भाषाएँ (Languages) →

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

2. एक अन्य भाषा जो निम्नलिखित में से चुनी जाय-

(i) (a) हिन्दी (उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है।)

(b) प्रारम्भिक अंग्रेजी (जिन्होंने)

(c) उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने पहले स्तर पर अंग्रेजी पढ़ी है।)

(d) एक आधुनिक भारतीय भाषा - हिन्दी को अतिरिक्त

(e) एक आधुनिक विदेशी भाषा

(f) एक शास्त्रीय भाषा

(ii) (a) सामाजिक अध्ययन (b) सामान्य विज्ञान

(iii) निम्नलिखित सूची से एक विषय चुना जाए -

(a) कताई एवं गुनाई

(b) पकड़ी का काम

(c) धातु कार्य

(d) बागवानी

(e) टेल्डिंग

(f) मॉडलिंग

इसके अतिरिक्त निम्नविषयों में से तीन विषय चुनने होंगे ।

1. मानव शरीर - एक - शास्त्रीय भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं तर्कशास्त्र, गणित, संगीत, सहविज्ञान ।

विज्ञान - भौतिक विज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान, गणित ।

कृषि - वाणिज्य, कृषि, वन्ये कृषि ।

शिक्षण की विधियाँ :-

1. विद्यालय में शिक्षण की विधियों का उद्देश्य केवल सही ढंग से ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है वरन् बच्चों में कार्य की आदत उचित अभिवृत्ति और सुधारों में रुचि करना भी होना चाहिए ।
2. बच्चों में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और पूर्णता से करने की कक्षा उत्पन्न करना ।
3. बच्चों में सीखने के लिए सक्रियता और ज्ञान जिसे वे कक्षा कक्ष में व्यावहारिक उपयोग के अवसर प्रदान करें ।
4. बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए शिक्षण विधियों की प्रयोग करने के विवेक पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए ।
5. बच्चों को समूह में कार्य करने के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और समूह योजनाएँ एवं क्रियाएँ लागू करनी चाहिए ।

अनुशासन

1. अनुशासन की उन्नति की दिशा में शिक्षकों और बच्चों के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ़ होने चाहिए ।
2. सभी विद्यालयों में मनीटर्स और छात्र-परिषदों के रूप में स्वशासन प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

वार्षिक एवं मातृ-शिक्षा

वार्षिक शिक्षा विद्यालयों में केवल स्त्री-शिक्षा मात्र पर ही शिक्षा विद्यालय से जाकर ही जा सकती है तथा प्रबन्धकों एवं माता-पिता की सह्यति लेनी चाहिये।

परीक्षाएँ

1. वार्षिक परीक्षाओं की संख्या कम होनी चाहिए और शिक्षा विद्यालय प्रकार के परीक्षाओं में कठिन परीक्षाओं को लागू करने और प्रश्नों के प्रकार में भी परिवर्तन करने का विचार करना चाहिए।
2. वार्षिक एवं मातृ-शिक्षाओं में अन्तर्गत छात्रों के स्थान पर सांकेतिक प्रणाली अपनायी चाहिए।

शिक्षा विध

1. माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं प्रगति से सम्बन्धित मामलों में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य निकटतम सहयोग होना चाहिए।
2. माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक अंशदान आयकर कानून से मुक्त होना चाहिए।

विक्षेपता / गुण

आयोग द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों की निम्नलिखित गुण/विक्षेपताएँ हैं।

1. आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करके उसके अन्तर्गत दोषों का निरीक्षण से उल्लेख किया, तथा ठीक सुधार हेतु

सुझाव देकर आयोग ने इसे दोषपूर्ण मानने का प्रयास किया ।

2. देश की वर्तमान आवश्यकताओं एवं जन आवश्यकताओं के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों का विस्तार किया ।
3. देश के औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया ।
4. देश की भाषा कलाकर्मों के समाधान हेतु भाषाओं के अध्ययन पर सुझाव प्रस्तुत किए ।
5. पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए विशेष ध्यान दिया ।
6. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि के विशेष महत्व होने हुए माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान देने एवं ग्रामीण कृषि विद्यालय खोलने का सुझाव दिया ।

दोष

1. आयोग ने विभिन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीन भाषाएँ एवं 4 आन्तरिक विषय होते हुए अन्य सबूट के पढ़ने की संरुति से पाठ्यक्रम बोझिल हो गया है।
2. स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किए ।
3. आयोग ने अंग्रेजी भाषा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया ।